कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–3/101/2016/10–11/10/1665 भोपाल, दिनांक 24-05-18

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–बुरहानपुर जिले के अंतर्गत भावसा मध्यम सिंचाई तालाब निर्माण हेतु 275.04 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-54/2017-FC दिनांक 05.03.2018

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी सैद्वांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

S.No.	Description	Compliance
2 (i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है।
2 (ii)	Compensatory afforestation over the non-forest land, equal in extent to the area of forest land being diverted, shall be raised within a period of three years with effect from the date of issue of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department at the cost of the user agency;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। आवेदक विभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि बुरहानपुर तथा कटनी जिलों में उपलब्ध कराई गई है।
2 (iii)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale;	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ इस जानकारी को उपलब्ध कराया गया है।
2 (iv)	The State Government will submit rehabilitation plan for 42 villagers along with the consent of the persons involved for relocation before stage-II approval;	आवेदक विभाग अवगत कराया गया है कि इस प्रस्ताव में किसी परिवार को विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में केवल कृषि भूमि ही डूब में आ रही है। किसी व्यक्ति का मकान प्रभावित नहीं हो रहा है।

2 (v)	The State Government will submit the Compliance of FRA of, 2006, in prescribed format in accordance with Ministry's guidelines dated 05.07.2013;	आवेदक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (vi)	The State Government will submit the Cost Benefit analysis in accordance with the Ministry's Guidelines dated 01.08.2017;	आवेदक विभाग द्वारा यह गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (vii)	The State Government will submit the duly approved CAT plan with the estimates;	विभाग द्वारा केट प्लान स्वीकृत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (viii)	The State Government will submit duly approved Wildlife Management Plan for affected area;	विभाग द्वारा वाइल्ड लाईफ मेनेजमेंट प्लान स्वीकृत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (ix)	No activities related to construction activities related to the Dam will be started without stage-II clearance under section 2(1i) of FC Act;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (x)	The non-forestland identified for CA will be transferred in favour of Forest Department and report submitted along with compliance report submitted for Stage-II clearance. The State Government will ensure that the CA land is free from any encroachment;	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है। नामांतरण संबंधी दस्तावेज वेब पोर्टल पर भी अपलोड है।
2 (xi)	Compensatory afforestation shall be raised over equal the diverted forest land and at least 1000 plants per hectare (277.13 ha x 1000=277130 plants) shall be planted over identified non-forest land and other degraded forest land as per the working plan prescription with provision for ten years on subsequent maintenance within three years of stage-II clearance. If it is not possible to plant that many saplings in the area identified for CA, the balance saplings will be planted in any other forests as per prescriptions of approved working plan;	आवेदक संस्था से क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि प्राप्त कर ली गई है। भारत सरकार की शर्तों के अनुसार प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 1000 पौधे रोपित किये जायेंगे।
2 (xii)	25% of CA cost will be deposited extra by the user agency for soil and moisture conservation (SMC) activities on the CA land;	आवेदक संस्था से गैर वन भूमि में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के लिये क्षतिपूर्ति वनीकरण की 25 प्रतिशत राशि जमा करा ली गई है।
2 (xiii)	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्था से क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि प्राप्त कर ली गई है। प्राप्त राशि ई–पोर्टल के माध्यम से भुगतान की गई है।
2 (xiv)	The User Agency shall transfer the funds for the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 through online portal of Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;	आवेदक संस्था से नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि प्राप्त कर ली गई है। प्राप्त राशि ई–पोर्टल के माध्यम से भुगतान की गई है।
2 (xv)	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Saving Bank Account pertaining to the State concerned through online/e-payment mode only;	प्राप्त राशि ई–पोर्टल के माध्यम से भुगतान की गई है।

2 (xvi)	The non-forest land to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for raising Compensatory Afforestation shall be notified as reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act. The Nodal officer must report compliance within a period of 6 month from the date of grant of final approval and send a copy of the notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the local Forest Act as the case may be, to this Ministry for information and record;	आवेदक संस्था से प्राप्त गैर वन भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही शीघ्र कर ली जावेगी।
2 (xvii)	The User Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'hle Supreme Court of India;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xviii)	The User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	आवेदक विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
2 (xix)	The State Government of the Madhya Pradesh and the user agency shall implement Rehabilitation and Resettlement (R & R) of the project affected families, if any, in a time bound and transparent manner;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xx)	The tree felling in the forest area, so diverted, shall only be as per the actual requirement and with prior permission of the competent authority.	प्रकरण में वन विभाग द्वारा वृक्षों का विदोहन न्यूनतम संख्या में किया जावेगा।
2 (xxi)	The State Government shall ensure that the User agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxii)	Period of diversion for diverted forest area shall be 30 (thirty) years from the date of issue of Stage-II Clearance;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxiii)	The State Government shall ensure that there shall be no tree felling between FRL (Full Reservoir Level) and FRL - 4 meters and the forest land located between FRL and the FRI.- 4 meters may be afforested by planting appropriate indigenous tree species;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है। वन विभाग द्वारा इस शर्त का पालन करते हुये आवश्यक वृक्ष ही काटे जायेंगे।
2 (xxiv)	User agency shall provide free water for the forestry related projects;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxv)	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxvi)	The State Government shall ensure that no labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2(xxvii)	The State Government shall ensure that the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।

2 (xxviii)	The State Government shall ensure that the user agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxix)	Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxx)	The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxxi)	The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the User Agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxxii)	The State Government shall maintain the character of the project as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxxiii)	The State Government shall ensure that the user agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxxiv)	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 03.08.2009 read with letter dated 05.07.2013, in support thereof.	आवेदक विभाग द्वारा यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxxv)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests wildlife.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxxvi)	The User agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above conditions and also to the conditions stipulated in stage-I clearance to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
2 (xxxvii	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines and relevant NGT / Hon'ble Court Order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।

2 (xxxviii)	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage- I clearance;	आवेदक संस्थान द्वारा सभी भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से किये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तवार प्राप्त पालन प्रतिवेदन संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार, की अंतिम औपचारिक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

24/5/19
(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ–3/101/2016/10–11/10/1666 भोपाल, दिनांक 16-05-19

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश।
3. वनमण्डलाधिकारी, (सा0) वनमंडल बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

24/5/19
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

PROFORMA FOR VERICICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

1	Name of Regional Office	Bhopal
2	State/Distt/Forest Division to which the proposal relates	State : M.P. District : Burhanpur Division : Burhanpur
3	Name of User Agency, nature of proposal	WRD
4	nature and category of proposal	Irrigation
5	Proposal number	8-54/2017-FC
6	Extent of forest area involved	275.04 ha.
7	Whether original or extension	Original
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	NA
9	Date of Ist stage clearance	05/03/2018
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz,: (a) Compensatory Afforestation: (b) Additional CA (c) Specific soil and moisture protection (d) Penal CA (e) Catchment Area Treatment Plan & Wildlife Management Plan (f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas (g) Net Present Value (h) Any Other Charges /levies (Please specify)	a) 10,65,42,243/- b) N/A c) 2,38,41,893/- d) N/A e) 6,92,04,952/- f) N/A g) 22,08,57,120/- h) N/A
	Total	**42,04,46,208/-**

11		Whether payment made through challan of othervise in case of online payment details of challan				Through Challan		
12		Details of deposits						
S No.	Type of deposit (NPV/CA/IWMP/ Others (specify))	Whether by RTGS/DD/ NEFT (specify)	UTR / DD No.	Amount deposited (Rs.)		Date of deposit	Name of Bank from which amout transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	NPV /CA/ Specific soil and moisture protection/CAT	RTGS/ NEFT	-	NPV	22,08,57,120	28.03.2018	Corporation Bank , New Delhi - 110003	
				CA &	10,65,42,243	06.03.2019		Through E-Portal
			-	Specific soil and moisture protection	2,38,41,893			
				Total	**13,03,84,136**			
				CAT Plan & Wildlife Management Plan	6,92,04,952			
G. Total					**42,04,46,208**			

24/5/19

(Sunil Agarwal)
APCCF (Land Management)
& Nodal officer FCA
Madhya Pradesh, Bhopal